

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT (EXCLUDING RAILWAYS) FOR THE YEARS 1971-72

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE/वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Central Government (Excluding Railways) for the year 1971-72 (August, 1971)

EIGHTH REPORT (1971-72) OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश): सीमा शुल्क सम्बन्धी राजस्व आय, 1970 के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) के अध्याय 2 के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति (1971-72) के आठवें प्रतिवेदन की एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूँ।

THE FINANCE (NO 2) BILL, 1971—contd

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं सदन के सम्मानित सदस्यों का यह जो देश की आज विचित्र स्थिति है उसकी ओर थोड़े में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चाहे कितना ही अच्छा कानून बना लिया जाय मगर यदि उन कानूनों की ठीक तरीके से उपयोगिता के रूप में करने की स्कीम न हो तो उससे जनता का कल्याण नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन में कुछ लोग पहले ही से ऐसा अपने दिमाग को बनाकर आते हैं कि जब भी सदन में

कोई सत्य बात कही जाय तो उसपर हल्ला जरूर मचाये। इससे जनतंत्र नहीं चलता। जनतंत्र तो विचारों का आदान-प्रदान है। जो सही बात जहा है अगर उससे फिसल कर बहम होगी तो फिर वह जनतंत्रीय बहस नहीं है, वह हडभोग हो जाता है और फिर उसमें विचारों का आदान-प्रदान नहीं होता।

यह सरकार आज हम से कुछ टैकम लगाने का अधिकार चाहती है, कुछ टैकम बढ़ाने का अधिकार चाहती है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि इस सरकार में तर्क भी कर्तव्य-परायणता का ज्ञान है तो यह सरकार हमसे क्यों यह अधिकार चाहती है कि हम इसमें कुछ टैकम लगाने और कुछ टैकम बढ़ाने का अधिकार दे। इस सरकार के पाम पहले ही से काफी धन है और उसका सदुपयोग होना चाहिए। ऐसी सूरत में जब वित्त विधेयक पर बोलने के लिये ही हम खड़े हुये हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि इतने दिन होने के बाद भी जो 60 लाख रुपया नागरवाला के कांड के रूप में गया, उस रुपये के बारे में आज तक इस सरकार ने सफाई के साथ कोई चर्चा क्यों नहीं की। श्रीमन्, आप जानते हैं कि जब उस रुपये के बारे में बार-बार प्रधान मंत्री का नाम लिया जाता है तब भी प्रधान मंत्री के मुखारविंद से उस रुपये के सम्बन्ध में आज तक एक शब्द नहीं निकला जबकि गली-गली में, वूचे-वूचे में इस बात की चर्चा है कि चुनाव के लिये यह रुपया निकाला गया।

श्री उपसभापति राजनारायण जी, फाइनेंस बिल पर बोलिये।

श्री राजनारायण श्रीमन्, मैं फाइनेंस बिल के बारे में ही बोल रहा हूँ। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस देश का धन इतने